(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ राज्य सरकारों के सिवाय संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से अनुदान प्रदान करने की प्रथा शुरू कर दी है, यदि हां, तो कब से; और

(घ) इसका औचित्य क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारापू येरन्नायडु): (क) से (घ) जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, दस लाख कुओं की योजना, गंगा कल्याण योजना, इंदिरा आवास योजना जैसे कार्यक्रमों के तहत खर्च को केन्द्र और राज्यों के बीच 80:20 तथा अन्य योजनाओं जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला तथा बाल विकास योजना तथा सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम के मामले में खर्च को 50:50 के अनुपात के आधार पर वहन किया जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल तथा पश्चिम बंगाल राज्यों, जिनको निधियां राज्य सरकार की इच्छानुसार सीधे ही जारी की जाती है को छोड़कर उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत अनुदान की राशि राज्यों की जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को जारी की जाती है।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभभोगी

91. **श्री दलीप सिंह जूदेव:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के विदिशा, राजगढ़ और रायगढ़ जिलों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितने ग्रामीण लोग लाभान्वित हुए हैं और उनमें से पिछड़े तथा दलित लोगों का कितना प्रतिशत है;

(ख) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत कितनी महिलाओं को लाभ मिला है और उनमें से आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं का प्रतिशत कितना-कितना है; और

(ग) विदिशा, राजगढ़ और रायगढ़ जिलों में विकास की धीमी गति के क्या कारण हैं तथा विकास की गति तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारापू येरन्नायडु): (क) से (ग) वर्ष 1996-97 के दौरान मध्य प्रदेश के विदिशा, राजगढ़ और रायगढ़ जिलों में प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे (i) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ii) जवाहार रोजगार योजना (iii) सुनिश्चित रोजगार योजना (iv) दस लाख कुंओं की योजना (v) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित ग्रामीणों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:—

(I) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या						
	कुल	अनुसूचित जाति	%	अनुसूचित जनजाति	%	महिलाएं	%
1. विदिशा	2512	530	21.10	86	3.42	298	11.86
2. राजगढ़	2018	408	20.22	75	3.72	220	10.90
3. रायगढ़	9756	1413	14.48	4501	46.14	858	8.79
(II) जवाहर रोजगार योजना	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)						
1. विदिशा	6.18	2.13	34.47	1.11	18.00	2.00	32.86
2. राजगढ़	3.94	0.99	25.13	0.68	17.26	1.55	39.34
3. रायगढ़	10.82	1.11	10.26	6.35	58.69	1.73	16.00

(I) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम				सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या			
(III) सुनिश्चित रोजगार योजना							
1. विदिशा	असूचित	असूचित	—	असूचित	—	असूचित	—
2. राजगढ़	3.18	1.11	34.90	0.45	14.15	1.75	55.03
3. रायगढ़	19.03	2.86	15.03	10.49	55.12	5.[illegible]	31.21
(IV) दस लाख कुंओं की योजना संख्या							
1. विदिशा	270	140	57.85	16	5.93	असूचित	—
2. राजगढ़	86	29	33.72	29	33.72	असूचित	—
3. रायगढ़	786	132	16.79	394	50.13	असूचित	—
(V) इंदिरा आवास योजना				(निर्मित मकानों की संख्या)			
1. विदिशा	1342	603	44.93	263	19.60	असूचित	—
2. राजगढ़	885	278	31.41	239	27.00	असूचित	—
3. रायगढ़	5935	1589	26.77	2391	40.29	असूचित	—

इस प्रकार इन जिलों में इन योजनाओं के अंतर्गत विकास की गति सामान्यतः संतोषजनक है। पिछड़ा, दलित (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर) और आदिवासी महिला लाभार्थी से संबंधित सूचनाओं की केन्द्रीय स्तर मानिटरिंग नहीं की जाती है।

Evaluation of various Rural Works Programmes

92. SHRI JAGIR SINGH DARD:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government sector or the private sector has done any large scale scientific and systematic evaluation study to find out the contribution of the various Rural Works Programmes like JRY PMRY, EGS etc. in reducing unemployment and under employment;

(b) if so, the findings of these studies;

(c) if not, Government's plans to undertake such studies; and

(d) the steps being taken to reduce rural underemployment?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) Two round of concurrent evaluations in respect of Jawahar Rozgar Yojana (JRY) were made by the reputed & independent research institutions for the period January-December, 1992 and May, 1993 to June, 1994. The evaluation of Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY) is under execution. No evaluation study has been conducted in respect of EAS.

(b) The findings of the first and second rounds of concurrent evaluation show that 4 and 11 mandays of employment were received by a worker during the reference period i.e. the last 30 days preceding the date of the respective surveys.

(c) The evaluation of PMRY is under execution. The Ministry of Rural Areas & Employment has requested the Planning Commission to undertake the evaluation study in respect of EAS.

(d) Under-employment and unemployment are sought to be reduced through implementation of various rural development schemes including JRY and